most comes the constitutional position of the Governor; secondly, the powers and functions to be performed by the Governor, thirdly whether he can be recalled and how; fourthly, in the present context of new factors emerging in our political horizon, what are the new powers to be given to Governors and what are the powers to be deleted.

MR. CHAIRMAN : She can continue on the next day.

18.30 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION SOAP LABELS

श्री प्रो० प्र० त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारतवर्ष में जो हिन्दू और मुसलमान रहते हैं उनमें अच्छाई कहिये या बुराई कहिये, कुछ इस प्रकार की भावना है कि वे गाय और सुवर के मामले में अपनी विशेष धार्मिक भावनायें रखते हैं। उनकी इस भावनाओं की रक्षा कोई आज ही नहीं बल्कि इस देश के मुसलमान शासकों ने भी इन भावनाओं का ध्यान रखते हुए यहां पर अपना शासन किया। बाबर ने अपने लड़के हुमायूं से कहा था कि अगर भारतवर्ष में शासन करना है तो यहां पर गो-हत्या बन्द करना ताकि यहां के लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा हो सके। यही बात विक्टोरिया ने भी, सन् 1857 के पश्चात् जब गाय और सुअर की चर्बी प्रयोग की बात आई, तब कही थी कि यहां के लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने भी सेक्युलेरिज्म का नारा इसीलिए लगाया था कि हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. समान रूप से सभी की भावनाओं की रक्षा करेंगे। अनुच्छेद 25, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें भी यह दिया हुआ है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि यहां के रहने वाले सभी लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करे। लेकिन यहां पर टैलो, चर्बी आ रही है जिसमें गाय की चर्बी तो है ही। सरकार ने यहां पर 13 जनवरी, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5407 का उत्तर देते हुए बताया था कि गाय की चर्बी तो होती ही है, हो सकता है कि सुअर की भी चर्बी हो। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब उसमें गाय की चर्बी है, उस चर्बी से साबुन बनता है, अधिकांश फैक्टरीज़ में उससे साबुन बन रहा है तो हमारी प्रार्थना थी कि आप उन पैकेट्स पर लिखवा दीजिए कि चर्बी से यह साबुन बनाया गया है फ़िर जिन लोगों की जैसी धार्मिक भावना होगी, चाहेंगे तो खरीदेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं खरीदेंगे। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं थी। उस समय पर इस प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया था कि हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है और अगर आती तो हम उस पर विचार करते। जब इस प्रकार का उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया तो फिर उसका प्रतिरोध हुआ, भारत के कोने कोने से और वह भी छोटे-मोटे आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि डालमिया, ए० के० नेवता, श्री अनन्तशयनम आयंगर और श्री जयप्रकाश नारायण की ओर से--और इसी प्रकार से जगह जगह पर आपत्तियां की गई। इस विरोध के पश्चात् फिर जब टैलो का प्रश्न आया तो मन्त्री महोदय ने यहां पर यह आश्वासन दिया था :

> "It is well known that tallow is being used in most cases. Where it is not used it is much simpler to say so in the lables and marked soap. But we are not against any other system of marking it if it helps. We have no objection to examine the first part also, whether those which use tallow can also be labelled. These aspects will be examined.

तो सरकार ने यहां पर यह आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के पश्चात् अब मैं एक भेद की बात और बता रहा हूँ। सरकार

[श्री ओ० प्र० त्यागी]

ने तमाम साबुन बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को यहां से सर्कुलर भेजा कि अगर इस प्रकार से लेबिल लगा दिया जाये तो उसमें क्या आपत्ति है। इस विज्ञप्ति के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यहां से जो जवाब गया है ए० के० नेवता, बम्बई वालों को, उसमें आपने कहा है–अण्डर सेक्रेटरी ने उत्तर देते हुए लिखा है—

"I am directed to refer to your letter dated 28th September, 1968 on the above subject and to say that the Government have requested the Association of leading soap-makers–the Indian Soap and Toileteries Makers Association–to advice its members to indicate on the wrappers whetaher the soaps marketed by them containimal fat tallow or not A reply from the Association is awaited."

यह जवाब इन्होंने दिया है। अधिकांश लोगों ने इनको जवाब दिया कि अगर ऐसा लिख दिया गया तो हमारा साबुन बिकना ही बन्द हो जायेगा। मैं सबूत तो नहीं देना चाहता लेकिन मेरा आक्षेप है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस के पास डोनेशन्श आई हैं इसीलिए ये इस विषय को टालना चाहते हैं। अब आश्वासन देने के पश्चात् इन्होंने अपना पैंतरा बदला है। अब जवाब देते हुए भी इन्होंने कहा कि अधिकांश साबुन टैलो से ही बनता है। यह सभी जानते हैं, और जो तेल से साबुन बनाते हैं उन पर कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। इस लिए जो नहीं इस्तेमाल करना चाहें वह न करें यही आप की दलील थी। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा सभी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका प्रमाण देना चाहता हूं कि प्रोफेसर रंगा, जो बहुत तपे तपाये लीडर हैं, उन्हों ने कहा कि मुझे पहली बार पता चला है, मैं आज जाना हूं कि सूअर और गाय की चरबी से साबुन बन रहा है। आयंगर जैसे विद्वान को जब मालूम पड़ा तो उन्हों ने फौरन प्रोटेस्ट किया। और अधिकांश देश की जनता गांवों में रहती है, उस को जानकारी नहीं है। और मुझे विश्वास है....

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : हम देहात में रहते हैं, आप नहीं रहते होंगे।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं भी गांव का रहने वाला हूं, और ठेठ गांव का रहने वाला हूं और आज भी हल चलाता हूं। 99.9 रेकरिंग जनता को पता नहीं कि आज साबुन गाय की चरबी से बन रहा हैं। आप ने जो खास तौर से बात कही है कि इस बात को सब जानते हैं ठीक हैं, मैं आप से प्रश्न करना चाहता हूं, इस का जवाब देंगे कि धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। यह मूल आधार हमारे संविधान में है इस से आप इन्कार नहीं कर सकते हिन्दुओं की भावनाओं को आघात पहुँचा है इस चर्बी के प्रयोग से। मैं पूछता हूं कि अगर चर्बी से बने साबुन के पैकेट पर भी लिख दिया जाय कि ऐनीमल फैट से बना है तो कौन सी हानि होगी सरकार को या उन को जो बनाते हैं? इस के विपरीत आप ने इस का जवाब देते हुए कहा है कि कुछ साबुनों पर लिखा है, परन्तु उन पर बाइन्डिंग तो नहीं है। अगर बाइन्डिंग उन पर है तो इन पर भी बायन्डिंग क्यों नहीं है। अगर उन पर प्रतिबन्ध नहीं लिखने का तो यदि कल को वह नहीं लिखें तो क्या होगा?

तीसरा सवाल यह है कि जो बड़ी फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने तो नहीं लिखा। लेकिन जो हजारों, लाखों छोटे आदमी हैं, जो घरों में साबुन बनाते हैं, छोटी-छोटी फैक्ट्री चला कर जो होम इण्डस्ट्री के रूप में साबुन बना रहे हैं वह चर्बी से नहीं बना रहे हैं, तेल से बना रहे

हैं, तो उन के साबुन पर तो लिखा नहीं जायगा और इन्हों ने यह भ्रांति फैला दी कि जिस पर नहीं लिखा गया वह सब चर्बी से बना है, तो वह छोटे आदमी मारे जायेंगे। आप ने मार दिया बेचारे गरीब आदमियों को जो होम इण्डस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो उन गरीबों का क्या होगा जो टैलो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और पैकेट पर भी नहीं लिख पाते हैं।

दूसरी बात यह कि आप ने जो फैक्ट्री वालों को पत्र लिखा तो उन का क्या उत्तर आया, उस को सभा पटल पर रखने की कोशिश कीजिए।

आप उस अवस्था का जवाब दीजिए कि अगर कोई देहाती बेपढ़ा आदमी सरकार पर केस चला दे कि सरकार ने अपनी अदूरदर्शिता के कारण, बार-बार टोकने के पश्चात भी मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायी है और सरकार पर हरजाने का दावा करता है तब आप क्या करेंगे।

माननीय अशोक मेहता जी ने इसी सदन में जवाब देते हुए कहा था कि वर्तमान समय में सन 1967-68 में इस देश में 1,27,395 टन टैलो आया है जिस की कीमत 18 करोड़ रु० थी। और सरकार ने कहा है कि पी०एल० 480 में भी हमें मजबूरन चर्बी लेनी पड़ रही है। 18 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा यह साबुन पर खर्च कर रहे हैं। और उसी के जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि श्री अशोक मेहता जी ने एक चीज़ कही थी, उन्हों ने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। सिन्थेटिक डेट्रेजेन्ट पैदा करने के लिए। वह दो, तीन साल में हो जायेगा और फिर टैलो की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर डेट्रेजेन्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मैं जानना चाहूंगा कि वह सिन्थेटिक डेट्रीजेन्ट्स कब तक पैदा कर लेंगे जिससे कि यहां की पूर्ति हो सके।

एक सवाल मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस समय एक बहुत बड़ा खतरा देश के सामने आया हुआ है कि चर्बी का घी में मिलाना शुरू हो गया है। साबुन में कोई टैलो इस्तेमाल करे या न करे, बहुत से लोग साबुन इस्तेमाल न भी करें लेकिन यह जो टैलो को घी में मिला कर घी के रूप में बेचना शुरू कर दिया है यह एक बड़ी चिन्ता की बात है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि लोग इस तरह से घी में टैलो न मिला सकें इस के लिए सरकार ने क्या सावधानी बर्ती है ?

मेरा अन्तिम प्रश्न जिस का कि मैं जवाब अवश्य चाहूँगा वह यह है कि क्या इस चर्बी के मामले पर कोई भी पोलिटिकल पार्टी इस का अनुचित लाभ जनता को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का कर उठा सकती है या नहीं ? जैसा कि अभी आप ने कहा कि जनसंघ यह गोहत्या पर पाबन्दी लगाने के नाम पर वोट मांगता है तो इस तरह का एक गन पाउडर किसी भी पोलिटिकल पार्टी द्वारा इस्तेमाल करने के लिए आप देश में क्यों सुरक्षित रक्खे हुए हैं यह मैं आप से जानकारी विशेष रूप से चाहूंगा ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R CHAVAN) : Mr. Chairman, Sir, I have listened to the speech of my hon. friend with rapt attention. He raised certain points and ended by saying, it is a gun-powder which can be exploited by any political party. In a democracy, any political party can take up an issue and go to the people and, if they get the support, well and good.

The point is whether tallow, in the first place, contains cow tallow or pig tallow. It comes, as a matter of fact, in a mixture form when it is imported from foreign countries, particularly, under P.L.

[Shri D. R. Chavan]

480. It is very difficult to say whether a particular tallow contains cow fat or a particular tallow contains pig fat in it. But, in a way, it is an animal fat and this animal fat has been used all over the world. Most of the countries are using animal tallow in the manufacture of soap.

Now, what is the substitute for animal tallow ? There must be some substitute for animal tallow with which soap can be manufactured in the country. There are a number of customers who are to keep health and hygiene and, for those persons, it is necessary to manufacture soap. If tallow is not brought in here, what is the substitute for tallow ?

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I have no objection; don't side-track the issue.

SHRI D. R. CHAVAN : I am not side-tracking the issue. Please listen to me.

What is the substitute for tallow ? The substitute for tallow is hydrogenated oil or groundnut oil. I do not know whether my hon. friend knows about the fluctuations in production concerning the groundnut oil. The production of groundnut oil depends upon the production of groundnuts and the production of groundnuts depends upon favourable weather conditions and other things. If the tallow is completely stopped for the manufacture of soap, nearty about 1,50,000 tonnes of vegetable oil will be consumed for the manufacture of soap. You will remember that sometime in 1966 and 1967, the production of groundnuts went down considerably and the result was that the prices of groundnut oil which were Rs. 2000 per tonne shot up to Rs. 5,575 per tonne........

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मन्त्री महोदय कृपया मेरे सवालों के जवाब दें। मैं ने बैन लगाने के लिए कब कहा है ? उस का तो सवाल ही नहीं हैं। जो सवाल किये गये हैं उन्हीं का उत्तर दिया जाय।

SHRI D. R. CHAVAN : Please listen to me; I did not interrupt you.

Therefore, if tallow is stopped and the vegetable oil is used, then there will be a shortfall by about 1,50,000 tonnes of vegetable oil which is consumed by ordinary and poor people of this country. That is a food for the poor people of this country. At these high prices, these persons will not be able to purchase it. Therefore, tallow which had been used in the manufacture of soap during the last 20 or 30 years on a restricted scale, is being used on a larger scale now. This is the economic consideration which I have just mentioned.

My hon. friend said that if those persons who were manufacturing soap from tallow were asked to put on lable on the wreappers, a label to the effect that a particular soap contains tallow in it, then he would be satisfied. In that context, he made an argument pointing out article 25 of the Constitution. I think, I must read out article 25 of the Constitution. Article 25 says :

> "Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion."

This is a right to profess, practise and propagate religion. May I ask the hon. Member whether any restriction has been put by the Government saying that you should use this particular soap which contains tallow. Nobody is forcing you to purchase this.. .

श्री ओम प्रकाश त्यागी : यह धोखा है पब्लिक के साथ। उस को आप क्यों नहीं बतलाते ?

MR. CHAIRMAN : If the Minister wants to reply, he may; otherwise, he may continue his speech.

SHRI D. R. CHAVAN : The article of the Constitution, to which he drew the attention of the House, does not say that the people of the country should purchase a particular type of soap. There are other

kinds of soaps which are manufactured out of vegetable oil and on the wrappers it has been mentioned that the particular soap is manufactured out of vegetable oil. It is there on the label. Therefore, every man is free to make his own choice. I am not asking my hon. friends to purchase the soap which contains tallow. They can go and find out from the wrapper the soap which contains not tallow but vegetable oil......

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अगर वह भी न लिखें तो ?

SHRI D. R. CHAVAN : It is being mentioned.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA (Anand) : May I say for the information of the Minister that, in France, soaps are made from human waste, from sewage, and there nobody objects to it ?

SHRI D. R. CHAVAN : He made a reference to a letter written by the Ministry to the Soap and Toilet Makers' Association. Soaps are of different kinds--there are laundry soaps and toilet soaps. I believe, my hon. friend is referring to toilet soap. As a matter of fact, a reply to that letter has been received in the Ministry. My hon. friend said that there was some *gol mal* concerning the reply. I will read out the reply which has been received in the Ministry. There is no *gol mal* or anything of that kind. The letter says :

> "...I have written to Mr. Ramakrishnaiah giving the various steps that Tata Oil Mills and other members of ISTMA have taken in this matter. In this letter I have clarified that Tata Oil Mills have long since decided to market their 'Moti' soap as a vegetable oil based soap with proper markings on the package. This vegetable oil based soap is already available in the market. Hindustan Levers have also decided to make one of their toilet soaps from vegetable oils and this is expected to be in the market shortly."

It has come in the maket; it is called 'Maharani' soap. On wrapper it is mentioned that it does not contain tallow but it contains vegetable oil. The letter said :

> "I have also mentioned in my letter of 9th November that Tata Oil Mills are considering marketing of a detergent tablet under the name of Bonus which is free from animal fat and which can be freely used for all washing purposes".

I am mentioning only the relevant portions. It is not that this matter was not taken up. In certain supplementaries this issue was raised by hon. Members and an assurance was given on the floor of the House that the matter will be taken to the Manufacturers' Association concerning this point. Now the question is this. About the soap that is produced, the total quantity is 2,20,000 tons That is manufactured. A small quantity of soap of about 35,000 tons is used for toilet purposes. The soap that is produced by two major companies, Tata Oil and Lever Brothers is produced in large quantities; on that soap it has been mentioned that this soap does not contain any animal fat in it. Therefore it is not a question of saying that the religious rights or feelings of the people are affected. There is no question of any interference with the religious feelings of the people at all.

Therefore, Article 25 says that each man is free to profess, propagate his religion. Similarly each man is free to purchase a soap which contains animal tallow or a soap which contains vegetable oil. He made a reference to the name of Shri Ashoka Mehta and what he stated on the floor of the House. He said that the Government is thinking of maufacturing synthetic detergents. Now, synthetic detergents, as the House is well aware, do not contain either vegetable fat or animal fat. May I mention the total quantity of synthetic detergents that are produced in the Country ? I will give the figures on the basis of the capacity likely to be sanctioned during the Fourth Five-year Plan and the total quantity likely to be produced by 1973-74 when the licensed capacity goes into production. Now, Sir, in respect of synthetic detergents, the production figures are follows :

[Shri D. R. Chavan]

1964– 7,224
1965– 8,300
1966–11,?04
1967–16,547
1968–17,104

New, additional capacity is likely to be sanctioned and I may mention for the information of the hon Member that by 1973-74 by the end of the fourth five-year plan production of synthetic detergents will be between 80,000 to 100 000 tons in the country. If this is produced, naturally to that extent it is available to the people of the country for washing purposes and the import of animal tallow will be stopped and to that extent it will go down. Nobody is interested in getting that animal tallow from foreign country at the cost of foreign exchange. But the difficulty was created on account of shortfall in production of groundnut oil and soaring prices which were there and there were complaints that the prices of groundnut oil were scoring sky-high. As I mentioned, from Rs 2,000 per-ton, the price shot up to Rs. 5,575 per ton. This was the position. It was under economic consideration that that was done. About synthetic detergents, the hon, Member must have seen how it is increasing. Actually in 1968 it was near about 17,000 to 18,000 tons. By the end of the Fourth plan when the capacity comes to be installed the production will be between 80,000 and 100 000 tons. To that extent animal tallow for which we are spending our foreign exchange will be reduced completely. It is not good for any country to depend on import from some foreign country for an essential commodity like soap and nobody likes it. I personally do not like it. I also respect the sentiments of the hon. Member. But, under the circumstances, when two different varieties of soap are available, one containing tallow and the other not containing tallow, you are free to purchase according to your choice. Freedom is yours. Nobody is compelling. Government is not compelling. Even those producers do not compel you Nobody compels anybody to purchase a particular type of soap which contains tallow. I personally feel that with this the Hon. Member willl be satisfied and if he is not satisfied. I cannot help it. But I hope he will be satisfied.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अगर टैलो के बने साबुन पर लिख दिया जाय कि इस में चर्बी है, तो क्या हर्ज है ।

SHRI D R. CHAVAN : It is not a question of money. When there are two different varieties available, it is for the people of the country to make their choice. Why are you insisting like this ? There are people in this country who prefer soap with animal tallow.

श्री रामगोपाल शालवाले (चान्दनी चौक): सभापति महोदय, मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिये, जिससे कि आपको बाहर से चर्बी न मंगानी पड़े, आपने क्या प्रयत्न किये हैं ?

दूसरे-कितनी तादाद में चर्बी बाहर से आती है–दो साल पहले कितनी आती थी और आज कितनी आती है ? यदि आप साबुन के लेबल पर लिखवादें कि इस में चर्बी पड़ी है- तो इस में सरकार को क्या आपत्ति है ?

जैसे अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हम किसी को मजबूर नहीं करते कि वह चरबीवाला साबुन बरते, लेकिन जिसको पता ही नहीं कि इस साबुन में चर्बी है, वह क्या करे ? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि साबुन विक्रेता को लिखें कि वह अपने साबुन के लेबल पर लिखे कि इस में चर्बी है ।

श्री कवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि टैलो यानी चरबी सब देशों में साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है । लेकिन अध्यक्ष महोदय दूसरे देशों में गऊ या सूअर की चर्बी के मामले में राष्ट्रीय भावनायें नहीं हैं, यह केवल हमारे देश में है । हमारे संविधान ने भी कहा है कि गऊ हत्या बन्द होनी चाहिये, हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज में भी इसका उल्लेख है । सरकार ने इस सबन्ध में एक

समिति भी बनाई हुई है जो विचार कर रही है कि किस प्रकार से इस देश में गऊ हत्या का नन बन्द हो। वह समिति अभी भी काम कर रही है। आप नमक पर डयूटी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते–इस लिये कि देश की भावना नमक के साथ है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, इस लिये उस भावना की कद्र होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल यह है–चाहे साबुन मंहगा हो या सस्ता हो - इस सरकार को राष्ट्रीय भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये—यह सरकार गऊ और सूअर की चर्बी किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं करेंगे–ऐसा ब्लैंकेट-बैन क्यों नहीं लगाती ?

अगर सरकार ब्लैंकेट-बैन पूरी तरह से नहीं लगा सकती तो क्या आप कोई का न बना कर मैन्यूफैक्चरर्स को मजबूर करेंगे कि वे अपने साबुन पर लिखें कि इस में चर्बी इस्तेमाल की गई है। जिनमें इस्तेमाल नहीं की गई उनमें कुछ न लिखा जाय। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पालिसी एन्टी-सैक्यूलरिज्म की है, क्योंकि सैक्यूलरिज्म का मतलब है - हर एक धर्म की रक्षा करना सरकार का फर्ज है, धर्म के खिलाफ काम करना सैक्यूलरिज्म का मतलब नहीं है।

मेरा आखरी सवाल यह है—आपने बताया है कि चौथी पंच वर्षीय योजना में इस का मंगाना बन्द हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप कब तक इसको बिल्कुल बन्द कर देंगे? आज यह भी शिकायत आ रही है कि इस को घी के अन्दर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने कहा है कि ऐसा नहीं होता है। क्या सरकार इस चीज की दोबारा जांच करायेंगी - क्योंकि जितना टैलो इम्पोर्ट होता है, उस के मुकाबले में साबुन कम बनता है और इस का उपयोग कहीं और होता है। क्या सरकार इस बात की एन्क्वायरी करायेगी कि इस टैलो का इस्तेमाल कहीं घी में तो नहीं होता है ?

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): मेरा पहला सवाल यह है कि जो लेबिल लगाने की बात है कि इस साबुन में चर्बी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सरकार यह रास्ता अपनाती है और जो साबुन बनते हैं उन पर लेबिल लग गया तो फिर जैसी लोगों की भावनायें हैं उसकी वजह से उस साबुन की खपत भी कम हो जायेगी, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह हिसाब लगाया है कि उसके कारण साबुन का कितना कन्जम्शन कम हो जायेगा ? अभी जो साबुन बनता है उसका कन्जम्शन लेबिल लगाने से कितना कम हो जाएगा, क्या इस बात का हिसाब सरकार ने लगाया है ?

19 hrs.

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अगल बगल के देशों में भी साबुन एक्सपोर्ट करते हैं ? यदि करते हैं तो फिर लेबिल लगाने से साबुन के एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा ? एक्सपोर्ट घटेगा या बढ़ेगा ? कितना घटेगा या बढ़ेगा ? इस का अगर कोई हिसाब आप के पास हो तो बतायें ?

तीसरी बात यह है कि आप ने कहा है कि टैलो के अलावा भी कुछ तरह के साबुन बनने लगे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कितनी वैरायटीज हैं साबुन की जो कि टैलो से नहीं बल्कि ग्राउन्ड नट आयल वगैरह से बनती हैं ? वह कितने तरह के साबुन हैं और कितनी क्वानटिटी में ईयरवाइज पिछले सालों में बने हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मुझे दो सवाल आपके सामने रखने हैं। अभी मन्त्री महोदय ने यहां पर बतलाया कि हिन्दुस्तान लीवर्स और टाटा आयल कम्पनी ने एक एक साबुन ऐसे बनाये हैं जिनमें चरबी का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे महारानी है या मोती। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो उस पर लिख रहे हैं कि इस में चरबी नहीं है वह सही लिख रहे हैं

[श्री रामावतार शास्त्री]

या गलत लिख रहे हैं, उसकी जांच करने के लिये ग्राप के पास क्या मशीनरी है ?

दूसरी बात ग्रापने कही कि हम को बाहर से चरबी मंगवानी पड़ती है। परन्तु मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान में भी कुछ चरबी का उत्पादन होता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में कितनी चरबी का उत्पादन होता है ग्रौर उस का इस्तेमाल ग्राप कहां कहां किस काम में करते हैं ?

श्री शशि भूषण (खारगोन) : ग्रध्यक्ष महोदय, यह टैलो की चर्चा है, हमारे देश में पाकिस्तान में ग्रौर ग्रफ्रीकन देशों में ही सूग्रर ग्रौर गाय को मानने वाले या न मानने वाले लोग हैं, दुर्भाग्य की बात है कि इन्हीं देशों में इतने ग्रर्से से जो टैलो का इस्तेमाल होता है, जो इसके कारखानेदार हैं, वही लोग सबसे ज्यादा शोर भी करते हैं। ग्राजादी के पहले ग्रग्रेजी फौज को गाय का मांस गोविन एण्ड कम्पनी की ओर से ऐसे ही लोग सप्लाई करते थे जो कि ग्राज भी शोर ग्रधिक करते हैं। (**व्यवधान**) मैं डालमिया साहब की बात कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि, क्या साबुन पर लेबिल लगना सम्भव हो सकता है, लेकिन जो सिन्थेटिक डेटरजेन्ट वगैरह हैं उनको ही ग्राप टैलो की जगह पर बाहर ग्रायात करें तो उस में क्या नुकसान होगा। पी० एल० 480 के जरिये टैलो को मंगा सकते थे।

Shri D. R Chavan : The first point raised was regarding the steps being taken to increase the production of groundnut. The Agriculture Departments not only here but in the States are taking steps to increase not only production of groundnut, and from it the oil, but are making efforts in various other directions to see that the country becomes self-sufficient in a period of time. My hon. friend knows that ultimately production depends on one factor. So long we have not been able to make provision for irrigation facilities at least to 60 percent of the total land under crop, we have to depend on the vagaries of the monsoon. Therefore, there are bound to be fluctuations. This is my answer as regards the steps taken to increase production.

Then it was asked, what harm is there if an indication is given in the wrapper ? In present circumstances, the matter could be taken to the manufacturers and they could be persuaded to give an indication in the wrapper that the soap inside contains tallow. But they say that there are other soaps which do not contain tallow but vegetable oil and people could purchase the ones containing vegetable oil. For the time being, we have no legal powers to compel the manufacturers making soap which contain tallow to state that fact on the wrapper.

Then the honourable Member asked me about the total quantity of tallow that was imported during the last three years I think that when I answered a supplementary question on that day, I mentioned the figure and I repeat them again now for the information of the honourable Member. The figures for 1966-67 are 19552 tons compared to 1,27,395 tons for 1967-68. For 1968-69 the figures are 50.007 tons In 1967-68 we had to import about 1.27 lakh tons because at that time particularly the production of ground nut was so low that the prices of ground nut oil shot up from Rs. 2000 to Rs. 5,575. Had this quantity not been imported, and the manufacturers of soap would have been permitted to use vegetable oils and the price of both the soap and vegetable oils would have become so high that the consumers of soap would have had to pay nearly Rs. 25-35 crores by way of enhanced prices So the economic aspect also had to be considered ; it is no use bringing in the religious feeling as no point will be served by creating this controversy about religious feeling. The honourable Member is as much a Hindu as I am. He was referring to article 25 of the Constitution. Government is not taking any step which will hurt the feelings of the people. Therefore let us leave the matter at that and see that the synthetic detergents are produced in larger quantities.

My honourable friend asked me why they should not be imported. The economics

of it will have to be worked out. If we do so, we will find that it will be costlier to import them. So it is better to produce them in the country. At the moment we are producing 17,000 tons of detergents and with the establishment of the petro chemical complex and that of wax-crackers near about Barauni for which a provision of Rs. 10 crores has been made in the Fourth Plan, we shall be producing the basic raw-material for the manufacture of synthetic detergent which will be cheaper for the people to purchase and gradually tallow will go away. Shri Kanwar Lal Gupta asked what time it would take and I replied giving the time as the end of 1973-74. We shall then be producing 80,000–1,00000 tons of synthetic detergents. At that time the population of the country will also have increased. It increases at the rate 2.6 percent and some demographer has said that it was likely to stablise between 2.6 and 2.9 percent. If we take into account the explosive rate of population growth the demand is likely to grow and I shall be happy if synthetic detergents are manufactured in such quantities that it is not necessary for the country to import them.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : There are two more points complete ban because of national sentiment and enecting a law forcing the manufacturers to put a label.

SHRI D. R. CHAVAN : We can impose a complete ban on the import of tallow provided we can find a substitute for it in the shape of synthetic detergents. When they are produced in sufficient quantities to cater to the needs of the people of this country. I do not think that there will be any necessity to import tallow spending foreign exchange. No country likes to spend foreign exchange. We are trying to find out a substitute for imports. By the end of the Fourth Plan at least 80 to 90 percent of our need would be met by synthetic detergent.

AN HON. MEMBER : *Kanoon.*

SHRI D. R. CHAVAN : About *Kanoon*, I said there is no point in creating unnecessary work. I may point out that the total quantity of soap which is produced in the country is 2,12,000 tonnes. We have not got any figures as to what is the total quantity of soap which is produced in the unorganised sector, that is, the small scale sector. That may be the same quantity. Therefore, it is better to point out to the people of the country saying that a particular soap and a particular brand does not contain tallow and therefore the person is free to purchase it.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister tell us what is the production of tallow?

SHRI D. R. CHAVAN : About the production of tallow there is no organised production of tallow in the country. Therefore, we have not got any figures available with us concerning the production of tallow in the country. I hope the House willbear with me for a few more minutes. Myhon. friend over there said that tallow is likelyto be used or is being used as an adulterant in ghee. That question was answered on that day very elaborately and all the supplementaries on the point were also answered on that day. At that time I mentioned that the import of tallow is regulated and channelised through the State Trading Corporation [A] this tallow is allotted on the recommendations made by the Director General of Technical Development with whom all these units are registered. On the recommendations of the Director-General of Technical Development, the allocation of tallow is made by the State Trading Corporation.

Secondly, the question was about the guarantee or check that it is not being used and so on, I may mention for the information of the hon. Member that a tonne of laundry soap contains about 0 37 tonne of tallow, and a tonne of toilet soap contains about 0.52 tonne. This is the equation. Therefore, the Director-General knows what allocations have been made and then by applying this formula he will know whether in proportion to the allocation of tallow, the production of soap is there or not. That acts as a sort of check. He gets an annual return of tallow used and therefore that

[Shri D. R. Chavan]

acts as a sort of check on the utilisation of tallow, its use or misuse. Therefore, it is a sound check on which we can reasonably rely. (*Interruption*)

I gave an assurance on that day to the House that, on the basis of the information I have, tallow is not misused as an adulterant in ghee.

I think that with these remarks my hon. friends will be satisfied.

19.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 31, 1969 Chaitra 10, 1891 (Saka).